*मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' का शुभारंभ**

शक्तिकान्त दास

आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के दौरान मिशन 'हर भुगतान डिजिटल' का शुभारंभ देश में डिजिटल भुगतान को तेज करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) अपनी 18वीं वर्षगांठ मना रहा है (इसका गठन 7 मार्च, 2005 को किया गया था)। इस उपलब्धि पर डीपीएसएस की टीम को बधाई। वर्षों से हमारी भुगतान प्रणाली विकसित हुई है और अब हमारे पास तत्काल भुगतान की सुविधा के लिए चौबीसों घंटे कई प्रणालियां उपलब्ध हैं। भारत की भुगतान प्रणालियों के बारे में विश्व स्तर पर बात की जाती है और कई देशों ने भारत की सफलता की कहानी दोहराने में रुचि दिखाई है।

यह गर्व की बात है कि भारत में भुगतान प्रणालियों ने दिसंबर 2022 से हर महीने 1000 करोड़ से अधिक लेनदेन देखे हैं। यह हमारे भुगतान पारितंत्र की मजबूती और उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृति बताते हैं। हाल ही में; एक अखिल भारतीय डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण (90,000 उत्तरदाताओं को कवर करते हुए) से पता चला है कि 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है।

2016 में शुरू किया गया यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) के साथ-साथ भारत में व्यक्ति से व्यापारी (पी 2 एम) लेनदेन शामिल हैं, जो कुल डिजिटल भुगतान का 75 प्रतिशत है। यूपीआई लेनदेन की मात्रा जनवरी 2017 में 0.45 करोड़ से कई गुना बढ़कर जनवरी 2023 में 804 करोड़ हो गई है। इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेनदेन का मूल्य केवल 1,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 12.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) देश भर में डिजिटल भुगतान के उपयोग और निशान को और गहरा करेगा।

भुगतान पारितंत्र में विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां हैं जिन्होंने डिजिटल में स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने खुदरा दुकानों, किराना स्टोअर्स, स्ट्रीट वेंडरों आदि जैसे व्यापारियों को पूरे देश में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने परेशानी मुक्त और सुव्यवस्थित डिजिटल बिल भुगतान अनुभव के साथ नकद / चेक से डिजिटल मोड में बिल भुगतान का स्थानांतरण सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली ने टोल प्लाजा पर कम प्रतीक्षा समय के संदर्भ में दक्षता बढ़ाने के साथ टोल भुगतान को डिजिटल मोड में स्थानांतरित करने में मदद की है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) प्रणाली ने सरकारी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) भुगतान को डिजिटल रूप से सुविधाजनक बनाया है और प्रणाली में रिसाव को समाप्त किया है। प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत 8.34 करोड़ किसानों तक प्रधानमंत्री द्वारा डीबीटी लाभ सुचारू रूप से पहुंचाना हमारी भुगतान प्रणालियों की निर्भरता और वितरण क्षमता का प्रमाण है।

हमने अपनी भुगतान प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत तथा सिंगापुर की फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई-पे नाउ के सीमा पार लिंकेज के लिए कदम उठाए हैं। यह लिंकेज क्यूआर कोड आधारित और यूपीआई सक्षम पी 2 एम भुगतान के अतिरिक्त है जो पहले से ही भूटान, सिंगापुर और यूएई में हो रहा है। हाल ही में, हमने जी 20 देशों के आगंतुकों को भारत में बैंक खाता खोले बिना यूपीआई में शामिल होने में सक्षम बनाया। इस पहल के जरिए, जी 20 प्रतिनिधियों को भारत में अपने प्रवास के दौरान यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों को निर्बाध रूप से भुगतान करने का पहला अनुभव मिला।

मिशन "हर भुगतान डिजिटल" का उद्देश्य डिजिटल भुगतान की सुगमता और सुविधा को मजबूत करना और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल दायरे में लाने की सुविधा उपलब्ध कराना है। उपलब्ध डिजिटल भुगतान चैनलों को उजागर करने वाले विभिन्न अभियानों की योजना बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा बनाई जा रही है। यह देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करेगा। मुझे यह जानकर

* श्री शक्तिकांत दास, भारतीय रिज़र्व बैंक - 06 मार्च, 2023 - डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (6-12 मार्च, 2023) मिशन 'हर भुगतान डिजिटल', मुंबई का शुभारंभ।

भी प्रसन्नता हुई है कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के जी 20 विषय-वस्तु के अंतर्गत डिजिटल भुगतान की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी गतिविधियों को शुरू करेंगे।

मिशन हर भुगतान डिजिटल के तहत "डिजिटल भुगतान अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ" – "एडोप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर्स" का संदेश बहुत प्रासंगिक है और इससे लोगों के बीच अधिक जागरूकता निर्माण होने और उसके उपयोग की उम्मीद है।

एक बार जब उपभोक्ता डिजिटल भुगतान पारितंत्र से जुड़ जाते हैं, तो इसके फायदे - उपलब्धता, सुविधा, गति और सुरक्षा- ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे और डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाएंगे। यह संदेश आरबीआई के भुगतान विजन 2025 यानी "सभी के लिए ई-पेमेंट्स, हर जगह, हर समय" के साथ मेल खाता है । गौरतलब है कि इस विजन के अंतर्गत समावेशन को एक आधार के रूप में पहचाना गया है और अब प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों से इसे सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

हमने 75 गांवों को गोद लेते हुए और ग्राम स्तर के उद्यमियों की भागीदारी के माध्यम से 75 डिजिटल गांव संबंधी योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत और आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में, पीएसओ देश भर के 75 गांवों को गोद लेंगे और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में परिवर्तित करेंगे। वे इनमें से प्रत्येक गांव में डिजिटल भुगतान के लिए गांव के व्यापारियों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें उससे जोड़ने के लिए दो शिविर आयोजित करेंगे।

मैं उद्योग, भुगतान प्रणाली संचालकों, मीडिया, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं और अन्य - जैसे सभी हितधारकों से अपील करता हूं कि वे गैर-उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के गुणों के बारे में बताएं और देश के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बनाने के साथ "हर भुगतान डिजिटल" मिशन को पूरा करें।